



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 23 मई, 2006/2 ज्येष्ठ, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 मई, 2006

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6) 15/2006-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18-5-2006 को प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश संख्यांक 1) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

2006 का अध्यादेश संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अध्यादेश, 2006

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अध्यादेश, संक्षिप्त नाम। 2006 है।

2. हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 10,
10-क और
10-ख का
अन्तः
स्थापना।

10. प्रतिदाय.—सहायक आवकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला का भारसाधक आवकारी एवं कराधान अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, पट्टेदार या किसी अन्य व्यक्ति को, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदत्त पट्टा धन की किसी भी रकम का विहित रीति में प्रतिदाय करेगा, यदि इस प्रकार संदत्त पट्टा धन की रकम, इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा देय रकम से अधिक है :

परन्तु यह कि प्रतिदाय विधि व्यवस्था प्रास्थिति, प्राकृतिक विपत्ति या दैवकृत या अनिवार्य बाध्यता के कारण हुई किसी भी हानि की दशा में ही अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिदाय तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिदाय के लिए दावा, उस तारीख से, जिस को कि ऐसा दावा प्रोद्भूत होता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर न किया गया हो।

10-क. अपील.—इस अधिनियम के अधीन पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अपील प्राधिकारी को, ऐसे आदेश के पारित करने के साठ दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जिसे अपील प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक के अनुज्ञात करे, होगी।

10-ख. पुनरीक्षण.—आयुक्त स्वप्रेरणा से, किन्हीं कार्यवाहियों का, जो उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है या उसके द्वारा निपटाई गई है, कोई अभिखेल ऐसी कार्यवाहियों की वैधता और औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा या आदेश राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तो उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियां उस तारीख से जिसको कि ऐसा आदेश संसूचित किया गया था, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ही प्रयोक्तव्य होगी।

विष्णु सदाशिव कोकणे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

प्रधान सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला :

तारीख :

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 1 of 2006.

**THE HIMACHAL PRADESH TOLLS (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2006**

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Ordinance, 2006.

Short title.

9 of 1975

2. After section 9 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975, the following shall be inserted, namely :—

Insertion
of section
10, 10-A
and 10-B.

10 Refund.—The Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer incharge of the district either *suo-moto* or on an application shall, in the prescribed manner, refund to the lessee or any other person, with the prior approval of the Commissioner, any amount of lease money paid by such lessee or person under this Act, if the amount of lease money so paid is in excess of the amount due from him under this Act :

Provided that refund shall only be allowed to the lessee in the event of any loss sustained on account of law and order situation, natural calamity or by acts of God or force majeure ;

Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of one year from the date on which such claim accrues.

10-A Appeal.—An appeal shall lie to the appellate authority, appointed by the State Government in this behalf, against any order passed under this Act, within sixty days of the passing of such order or within such further period as the appellate authority may, for sufficient cause, allow.

10-B. Revision.—The Commissioner may, of his own motion, call for the record of any proceedings which are pending before, or have been disposed of by, any authority subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or the order being prejudicial to the interest of revenue, may pass such order in relation thereto as he may think fit :

Provided that powers under this section shall be exercisable only within a period of five years from the date on which such order was communicated.